गुजरात की ताला-चाबी गैंग के तीन शातिर बदमाश गिरफ्तार

जयपुर। मुरलीपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ताला-चाबी ठीक करने के बहाने घर मे घुस कर चोरी करने वाली गुजरात की ताता-चाबी गैंग के तीन शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास

- **चाबी बनाने के बहाने अलमारी से चुराते थे नकदी और जेवरात**
- **पुलिस ने जब्त किया चुराए गए सामान**
- **पुलिस पूछताछ में और भी कई वारदातें खुलने की आशंका**

से चुराया गया सोने-चांदी के जेवरात सहित नकदी बरामद की है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर (पश्चिम) अमित कुमार ने बताया कि मुरलीपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ताला-चाबी ठीक करने के बहाने घर मे घुस कर चोरी करने वाली गुजरात की ताता-चाबी गैंग के शातिर बदमाश सरदार सतनाम सिंह (29) निवासी दाहोद गुजरात, सन्नी सिंह उर्फ सरदार सन्नी देवल (30) निवासी दाहोद गुजरात और सरदार राजेन्द्र सिंह (35) निवासी कोतवाली डूंगरपुर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों से चोरी

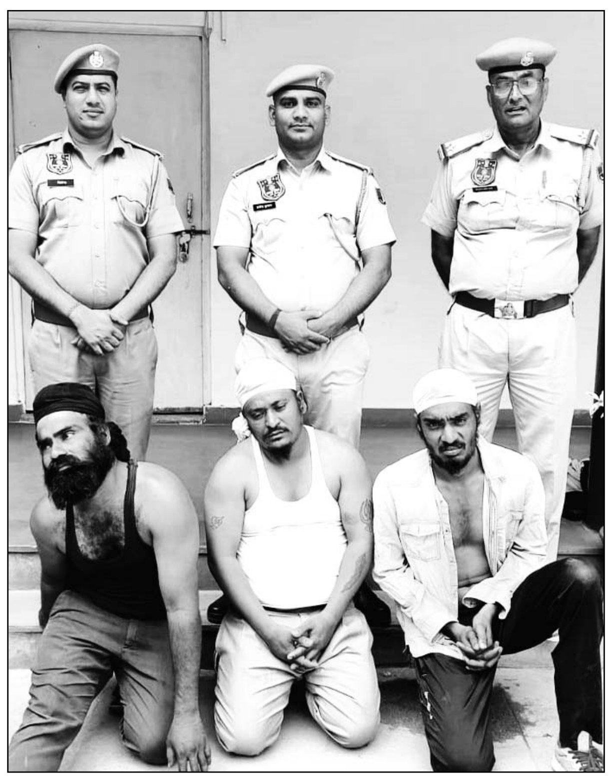

मुरलीपुरा थाना पुलिस ने ताला-चाबी ठीक करने के बहाने घर में घुस कर चोरी करने वाली गुजरात की ताता-चाबी गैंग के तीन शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है।

का माल एक आर्टिफिशियल चैन, एक आर्टिफिशियल मंगलसूत्र, अन्य आभूषण एवं आधार कार्ड-की बरामद किया गया है। पुलिस पूछताछ में और भी कई वारदातें खुलने की आशंका जताई जा रही है।

थानाधिकारी वीरेंद्र कुरील ने बताया कि वारदात करने के लिए गुजरात से आकर होटल में ठहरते थे और गैंग के सदस्य कॉलोनियों में पैदल घूमते हुए ताले-चाबी ठीक करने का बहाना कर वारदात करते थे। घर में अकेली महिला या सुनसान मकान देखकर दो सदस्य घर के अंदर जाते हैं और एक बाहर निगरानी रखता है। अंदर जाकर अलमारी का ताला ठीक करने के बहाने घरवालों का ध्यान भटकाते हैं और मौका देखकर कीमती सामान चुराकर फरार हो जाते हैं। सीसीटीवी से हुई पहचान पुलिस ने बताया कि आरोपियों को पकडने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम ने 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले। आरोपियों की गतिविधियां कैमरों में कैद हुई। जिन्हें ट्रेस कर पुलिस ने उन्हें दादी का फाटक क्षेत्र से गिरफ्तार किया।

पुलिस उनसे अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ कर रही है, जिससे कई और चोरी की वारदातों का खुलासा होने की संभावना है।

पुलिस ने आमजन से अपील की है कि अज्ञात व्यक्तियों को घर में प्रवेश न दें और ताला-चाबी बनाने वाले फेरीवालों से सतर्क रहें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना नजदीकी थाने को दें।

लू-तापघात प्रबंधन के लिए हर जिले में होगा सघन निरीक्षण

जयपुर। राज्य में लू-तापघात की स्थितियों के दृष्टिगत दवाओं की निर्बाध एवं समुचित आपूर्ति तथा चिकित्सा उपकरणों की क्रियाशीलता को लेकर राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन की ओर से ग्रीष्मकालीन सघन निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। अभियान के लिए 27 टीमों का गठन किया गया है।

उल्लेखनीय है कि विगत दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में लू-तापघात की स्थितियों में आमजन के स्वास्थ्य को लेकर पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। इन निर्देशों की अनुपालना में चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के मार्गदर्शन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से लू-तापघात से बचाव एवं उचपार आदि के संबंध में जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

आरएमएससीएल की प्रबंध निदेशक नेहा गिरि ने बताया कि राज्य में हीटवेव की सम्भावनाओं को देखते हुए ग्रीष्मकालीन सघन निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। निगम में कार्यरत विशेषाधिकारी, समस्त कार्यकारी निदेशक, लेखाधिकारी तथा जिला औषधि भण्डार गृह के प्रभारी अधिकारी को जिलों का आवंटन कर यह निरीक्षण करवाए जाएंगे। इसके लिए दो सदस्यीय 27 टीमों का गठन किया गया है। यह टीमें निरीक्षण कर जिले में औषधियों, उपकरणों की उपलब्धता एवं क्रियाशीलता को लेकर 30 मई तक अपनी विस्तृत रिपोर्ट देंगी।

सामूहिक पंजीकरण शिविर में श्रमिकों को जारी हुए ई-श्रम

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर-प्रथम व द्वितीय के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को हीरापुरा चौराहा 200 फीट बाईपास स्थित मजदूर चौखटी पर सामूहिक पंजीकरण शिविर का आयोजन किया गया।

जयपुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर जिला, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर-प्रथम व द्वितीय के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को हीरापुरा चौराहा 200 फीट बाईपास स्थित मजदूर चौखटी पर सामूहिक पंजीकरण शिविर का आयोजन किया गया। श्रम विभाग, कॉमन सर्विस सेन्टर, ट्रेड यूनियन, एक्शन एड तथा आजीविका एनजीओ के सहयोग एवं समन्वय से आयोजित शिविर में 63 श्रमिकों का मौके पर ही ऑनलाईन ई-श्रम कार्ड जारी किया गया, साथ ही 65 श्रमिक कार्ड फार्म भरवाए गए एवं 200 से अधिक श्रमिक हाजिरी डायरी वितरित की गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर जिला के सचिव पवन कुमार जीनवाल तथा दीपेन्द्र माथुर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर प्रथम ने चौखटी पर उपस्थित श्रमिकों को उनके विधिक अधिकारों, श्रम विभाग की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की।

जीनवाल ने यह भी बताया कि जो श्रमिक शिविर में ऑनलाइन पंजीकरण से वंचित रह जाएंगे, उनके लिए बुधवार को विश्वकर्मा रोड नम्बर 14 सीकर रोड स्थित मजदूर चौखटी तथा 8 मई को इंडिया गेट सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित मजदूर चौखटी पर भी ऑनलाइन पंजीकरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। पंजीकरण हेतु श्रमिकों को आधार कार्ड, बैंक पासबुक तथा मोबाइल साथ लेकर मौके पर आना होगा। शिविर में श्रमिकों को श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं जैसे निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना, निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना, सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना, हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना, प्रसूति सहायता योजना, शुभशक्ति योजना, निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना, निर्माण श्रमिक औजार /टूलकिट सहायता योजना, निर्माण श्रमिक एवं उनके आश्रित बच्चो द्वारा भारतीय/राजस्थान प्रशासनिक सेवा हेतु आयोजित प्रारम्भिक प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन योजना एवं अन्य योजनाओं की विस्तुत जानकारी प्रदान की जाएगी।

शिविर के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर जिला से पीएलवी श्री सुरेश कुमार गुर्जर ने श्रमिकों का ऑनलाईन पंजीकरण करने में सहायता प्रदान की। शिविर के दौरान पल्लवी शर्मा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर-द्वितीय, श्रम विभाग से भारती भिण्डा, अनुपम गौतम, सीएससी से सुरेन्द्र कुमार जांगिड तथा दीपक जांगिड, ट्रेड यूनियन से अनिल बैरवा तथा तुषार बैरवा, एक्शन एड एनजीओ से मूलचंद शर्मा तथा हेमलता व अन्य उपस्थित रहे।

कुसुम योजना में एक हजार मेगावाट ऊर्जा उत्पादन क्षमता का नया कीर्तिमान बनाया

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सौर ऊर्जा क्रांति का साक्षी बनता राजस्थान**
- **1 लाख 70 हजार से अधिक किसानों को दिन में मिलने लगी बिजली**

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सौर ऊर्जा का सूर्य निश्चित तौर पर देश के पश्चिमी राज्य राजस्थान में चमक रहा है। सूर्य भगवान की विशेष कृपा से प्रदेश की सुनहरी रेतीली धरती में सौर ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं, जिनके दोहन के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहले दिन से ही निरंतर प्रयासरत हैं।

राजस्थान को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य की दिशा में पीएम-कुसुम योजना के माध्यम से एक बड़ी कामयाबी मिली है तथा राजस्थान ऐसा अग्रणी राज्य बन गया है जहां इस योजना के कम्पोनेंट-ए एवं कम्पोनेंट-सी के अन्तर्गत सौर ऊर्जा उत्पादन 1 हजार मेगावाट से अधिक हो गया है। सौर ऊर्जा का उपयोग कर किसानों को दिन में बिजली आपूर्ति की दिशा में भी राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है जिससे आज प्रदेश में 1 लाख 70 हजार से अधिक किसानों को दिन में बिजली सुलभ होने लगी है। पीएम कुसुम योजना के कम्पोनेंट-ए एवं कम्पोनेंट-सी के तहत ही 560 ग्रिड कनेक्टेड विकेन्द्रित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर 70 हजार से अधिक कृषि उपभोक्ताओं को दिन में बिजली दी जा रही है। वहीं इस योजना के कम्पोनेंट-बी में लगभग 1 लाख किसानों के कृषि पम्पों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जा चुका है। राज्य द्वारा योजना के सफल क्रियान्वयन को देखते हुए भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुसुम-ए में दो बार में कुल 6 हजार मेगावाट क्षमता के संयंत्रों के अतिरिक्त आवंटन को स्वीकृति दी है तथा कम्पोनेंट-सी में 2 लाख सोलर पम्पों का अतिरिक्त आवंटन किया है। इस प्रकार इस योजना में प्रदेश में लगभग 12 हजार मेगावाट क्षमता के प्लांट स्थापित किए जाने का लक्ष्य रख कार्य किया जा रहा है।

पूर्ववर्ती सरकार के अंतिम तीन सालों में जहां केवल 92 प्लांट ही स्थापित किए जा सके थे। वहीं आज प्रदेश में कम्पोनेंट-सी में लगभग हर दिन औसतन एक नया सौर ऊर्जा संयंत्र ग्रिड से जुड़ रहा है। बीते 6 माह में प्लांटों के क्रियाशील होने की गति में और तेजी आई है। इस अवधि में कम्पोनेंट-ए में 183 मेगावाट क्षमता के 134 तथा कम्पोनेंट-सी में 514 मेगावाट क्षमता के 196 प्लांट स्थापित हुए हैं। यह प्रगति इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि जबसे यह योजना प्रारंभ हुई उसके बाद से ऊर्जा उत्पादन में प्रतिदिन औसतन चार से पांच मेगावाट क्षमता की अतिरिक्त बढ़ोतरी हो रही है।

योजना के तहत यह प्लांट मुख्यत: राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हो रहे हैं जहां कृषि कनेक्शन अधिक संख्या में हैं। खेत के समीप भूमि पर लग रहे अधिकतम 5 मेगावाट क्षमता तक के इन सौर ऊर्जा संयंत्रों से किसानों को खेती से जुड़े कार्यों के लिए दिन में बिजली सुलभ होने लगी है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यिमता के एक नए युग की शुरूआत हुई है। अपनी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर किसान अन्नदाता के साथ-साथ ऊर्जादाता भी बन रहे हैं जिससे उन्हें आमदनी का एक अतिरिक्त जरिया भी मिला है।

योजना में फीडर लेवल सोलराइजेशन के अन्तर्गत 33/11 केवी ग्रिड सब स्टेशन के लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाने का प्रावधान है। कंपोनेंट-ए में अधिकतम 2 मेगावाट क्षमता तक तथा कंपोनेंट-सी में अधिकतम 5 मेगावाट क्षमता तक के ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। कंपोनेंट-सी में सौर संयंत्र की स्थापना पर भारत सरकार लागत का अधिकतम 30 प्रतिशत (अधिकतम 1 करोड़ 5 लाख रूपए प्रति मेगावाट) तक अनुदान देती है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्ष-2027 तक किसानों को कृषि कार्य के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराने का संकल्प व्यक्त किया है। इस संकल्प को साकार करने की दिशा में यह योजना महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार द्वारा इसे फ्लैगशिप योजना के रूप में भी सम्मिलित किया गया है।

डिस्कॉम्स द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर सौर संयंत्रों की स्थापना में आने वाली बाधाओं को दूर किया गया। अवॉर्ड जारी होने के बाद पावर परचेज एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने, सौर संयंत्र को 11 केवी एवं 33 केवी प्रसारण लाइनों के माध्यम से ग्रिड से जोड़ने, ट्रांसफार्मर तथा मीटर से संबंधित स्वीकृतियों के कार्यों, सोलर प्लांट्स के निरीक्षण तथा साइट विजिट्स को विद्युत वितरण निगमों द्वारा निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जा रहा है। साथ ही जिला कलक्टरों को विद्युत लाइन बिछाने की राह में आ रही बाधाओं को दूर करने के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। योजना के फलीभूत होने का फायदा विद्युत वितरण निगमों को लगभग 3 रूपए प्रति यूनिट की सस्ती बिजली की उपलब्धता के रूप में मिल रहा है। स्थानीय स्तर पर पैदा होने वाली बिजली का उपयोग स्थानीय स्तर पर ही होने से प्रसारण में होने वाली छीजत भी कम हुई है। साथ ही, कृषि की बढ़ती मांग की आपूर्ति के लिए विद्युत निगमों को अतिरिक्त विद्युत तंत्र विकसित करने की आवश्यकता में भी कमी आई है। डिस्कॉम्स को अब कृषि कार्य के लिए एक्सचेंज से महंगे दाम पर बिजली खरीदने की आवश्यकता नहीं होती। सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 1 हजार मेगावाट बिजली अतिरिक्त उत्पादन क्षमता विकसित करने में राज्य सरकार के बजट पर कोई अलग से भार नहीं आया है एवं साथ ही, कार्बन फुटप्रिंट में भी कमी आ रही है। योजना के कम्पोनेंट-बी का क्रियान्वयन उद्यानिकी विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत वर्तमान राज्य सरकार द्वारा 39 हजार से अधिक सौर ऊर्जा पम्प संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है एवं इस दृष्टि से राजस्थान देश में प्रथम तीन राज्यों में है। कम्पोनेंट-बी में किसानों को 3 से 7.5 हॉर्स पावर क्षमता के सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापित करने पर 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

दिल्ली-एनसीआर में पटाखे बैन

जयपुर। उच्चतम न्यायालय के द्वारा एस.सी. मेहता बनाम भारत संघ व अन्य के केस में दिए गए निर्णय की पालना में राज्य के गृह विभाग ने राज्य के दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में सम्पूर्ण वर्ष पटाखे चलाने, इसके विनिर्माण, संग्रहण, विक्रय (जिसमें ऑनलाइन विक्रय भी शामिल है) और वितरण को प्रतिबंधित कर दिया है।

एबीवीपी ने युवाओं को मॉक ड्रिल से जुड़ने को कहा

जयपुर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 7 मई को केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित "सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल" में भाग लेने की घोषणा की है और देशभर के युवाओं-विद्यार्थियों से इसमें सक्रिय सहभागिता का आव्हान किया है। हालिया पहलगाम आतंकी हमले और बढ़ते सुरक्षा खतरों के मद्देनज़र यह अभ्यास अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इस मॉक ड्रिल में एयर रेड सायरन, ब्लैकआउट अभ्यास, नागरिकों की सुरक्षित निकासी और आपात सुरक्षा प्रशिक्षण शामिल हैं। साथ ही महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के संरक्षण हेतु कैमोफ्लाज तकनीकों का अभ्यास भी किया जाएगा।

एबीवीपी का मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा हर नागरिक, विशेषकर युवाओं की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसलिए विद्यालय व महाविद्यालय परिसर को जागरूकता व सतर्कता के केंद्र बनाना होगा। अभाविप जयपुर प्रांत मंत्री अभिनव सिंह ने कहा, सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल देश की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रदेश के सभी छात्रों, शिक्षकों व नागरिकों से आग्रह करते हैं कि वे इस मॉक ड्रिल में उत्साहपूर्वक भाग लें और सुरक्षित, सशक्त एवं आत्मनिर्भर भारत की दिशा में योगदान दें। एबीवीपी प्रदेशभर के कॉलेजों में पहलगाम घटना के विरोध में पोस्टकार्ड व हस्ताक्षर अभियान चलाएगी।

कांग्रेस की बैठक में अर्चना शर्मा ने दिखाया नेताओं को आईना

- **'भीड़ लाने वालो को सम्मान दिया जाना जरूरी, निष्क्रिय को दिखाओ बाहर का रास्ता'**

जयपुर। जयपुर कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली की तैयारी के लिए बुलाई गई जयपुर शहर कांग्रेस की बैठक मे मालवीय नगर से कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना शर्मा ने रैलियों में भीड़ लाने वालो को मंच से नीचे और अकेले आने वालों को मंचों के सामने जगह मिलने पर नाराजगी जताई।

अर्चना शर्मा ने जयपुर प्रभारी धर्मेंद्र राठौड़ पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आपने 28 अप्रैल की रैली से पहले कहा था कि मैं सब नेताओं की भीड़ की गिनती करूंगा कौन कितनी भीड़ लाया, लेकिन आपने वो काम नहीं किया यह गलत बात है। इस दौरान जयपुर के संगठन महामंत्री सीताराम नेहरू ने उन्हें टोका तो अर्चना ने कहा कि आप मुझसे ज्यादा मंच संचालन करना नहीं जानते हैं। मैंने 10 साल तक प्रदेश कांग्रेस का मंच संचालन किया है। अर्चना शर्मा ने कहा कि रैली में रफीक खान भीड़ लेकर आए अमीन कागजी भीड़ लेकर आए। मालवीय नगर से भी अच्छी भीड़ थी। लोग कहते हैं कि अर्चना शर्मा तो मालवीय नगर में खत्म हो गई हैं। मैं भले ही चुनाव हारी हूं, लेकिन संगठन को कमजोर नहीं होने दिया है। अर्चना शर्मा ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा है। जो कार्यकर्ता सक्रिय रूप से संगठन में काम करता है, उसको पहचानना पड़ेगा। उसको सम्मान देना पड़ेगा और जो काम नहीं करता है उसको भी पहचानना होगा। अर्चना शर्मा ने कहा कि मैं 2018 के चुनाव में लगभग जीत चुकी थी, कुछ भी वोटों का अंतर रह गया था। 2023 के चुनाव में भले ही मैं हार गई हूं, लेकिन मैंने संगठन को कमजोर नहीं होने दिया है।

इस दौरान जयपुर शहर अध्यक्ष आरआर तिवाड़ी ने कहा कि जयपुर शहर कांग्रेस की बैठक में तो सभी को सम्मान मिलता है, चाहे वो ब्लॉक अध्यक्ष हो या फिर मंडल अध्यक्ष। कार्यकारिणी के लोग हों या फिर पार्षद दल का नेता हो, सभी को सम्मान मिलता है। प्रदेश कांग्रेस की अलग बात है। प्रभारी धर्मेंद्र राठौड़ ने बैठक में गैर हाजिर पदाधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी पदाधिकारी लगातार तीन बैठकों में नहीं आएगा, उसे संगठन से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा।

'कोई भी संदिग्ध भ्रष्टाचारी पाया गया तो दंडात्मक कार्यवाही होगी'

नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के मुख्य सतर्कता अधिकारी अमित कुमार शर्मा, वरिष्ठ एवं अतिरिक्त मुख्य सतर्कता अधिकारी तरुण कुमार जैन के द्वारा एनएफएल राज्य कार्यालय, जयपुर में भ्रष्टाचार के प्रति जागरूकता एवं रोकथाम पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

जयपुर। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) के मुख्य सतर्कता अधिकारी अमित कुमार शर्मा, वरिष्ठ एवं अतिरिक्त मुख्य सतर्कता अधिकारी तरुण कुमार जैन (मुख्य प्रबंधक, सतर्कता) के द्वारा एनएफएल राज्य कार्यालय, जयपुर में भ्रष्टाचार के प्रति जागरूकता एवं रोकथाम पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में कंपनी के प्रति समर्पित विभिन्न जिलों के थोक विक्रेताओ एवं राज्य कार्यालय राजस्थान के अधिकारियो एवं कर्मचारियो ने भाग लिया। बैठक के दौरान अमित कुमार शर्मा, के द्वारा बैठक मे सम्मिलित एनएफएल के समस्त थोक विक्रेताओ, अधिकारियों एवं कर्मचारियो को भ्रष्टाचार उन्मूलन के बारे मे विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई ताकि भ्रष्टाचार रहित संस्थान का उद्देश्य चरितार्थ हो एवं सभी को किसी भी प्रकार की गतिविधियों मे भ्रष्टाचार न करने के लिए आदेशित किया गया। एनएफएल के समस्त थोक विक्रेताओं, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भ्रष्टाचार विरोधी एवं सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा दिलाई गई। उन्होंने कहा कि कोई भी थोक विक्रेता, अधिकारी एवं कर्मचारी किसी भी प्रकार की गतिविधि में भ्रष्टाचार संदिग्ध पाया गया तो उसके खिलाफ दंडात्मक एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

खानों के माइनिंग प्लान का ऑनलाईन अनुमोदन शुरु : टी.रविकांत

जयपुर। राज्य के खान विभाग ने खानों के माइनिंग प्लान व माइनिंग योजनाओंके ऑनलाईन अनुमोदन की प्रक्रिया शुरु कर दी है। प्रमुख सचिव माइन्स, भूविज्ञान एवं पेट्रोलियम टी. रविकान्त ने बताया कि राज्य सरकार ने माइनिंग सेक्टर में सरलीकरण और पारदर्शी व्यवस्था की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए पिछले दिनों एक मई से माइनिंग प्लान व माइनिंग योजनाओं का ऑनलाईन अनुमोदन का निर्णय किया था। उन्होंने बताया कि ऑनलाईन अनुमोदन की प्रक्रिया आरंभ हो गई है और जयपुर, ब्यावर, सिरोही, बारां, बांसवाड़ा और चुरु में लाइमस्टोन बर्निंग, मेसेनरी स्टोन, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन क्रशर और क्वार्टज फेल्सपार के माइनिंग प्लान व माइनिंग योजनाएं अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गई है।

टी. रविकान्त ने बताया कि नई व्यवस्था से करीब 30 हजार अप्रधान खनिज लीजधारक और क्वारी लाइसेंसधारक लाभान्वित हो सकेंगे। अब उन्हें योजनाओं के अनुमोदन के लिए खनिज विभाग के कार्यालयों में चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अप्रधान खनिजों के माइनिंग लीजधारकों व क्वारी लाइसेंसधारकों को माइनिंग प्लान व माइनिंग स्कीम का अनुमोदन करवाना होता है। नियमानुसार विभाग द्वारा 90 दिवस में अनुमोदन की कार्रवाई पूरी करनी होती है पर अनुमोदन में इससे अधिक समय भी लग जाता है।

बुधवार को प्रस्तावित मॉक ड्रिल की तैयारियों समीक्षा की सी.एस. ने

जयपुर। वर्तमान परिदृश्य में राज्य में नागरिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण एवं क्रियाशीलता के आकलन हेतु केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों की पालना में मंगलवार को मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में राज्य के समस्त संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक एवं सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारियों की वीसी के माध्यम से बैठक आयोजित की गई।

सचिवालय में आयोजित बैठक में बुधवार को प्रस्तावित मॉक ड्रिल एवं ब्लैक आउट हेतु संबंधित जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि सभी संचार माध्यमों एवं सायरनो को तुरंत दुरुस्त किया जाकर संचार प्रणाली का सुदृढीकरण सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में गृह एवं आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा, जल संसाधन एवं पीएचईडी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व स्वायत्त शासन विभागों के प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा विभागों के शासन सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, पुलिस महानिदेशक राजस्थान, महानिदेशक इन्टेलिजेन्स, महानिदेशक गृह रक्षा, प्रबंध निदेशक, जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़, प्रबंधक, उ.प. रेलवे जयपुर, कमाण्डेंट, राज्य आपदा प्रतिसाद दल, ग्रुप कैप्टन, एयर फोर्स स्टेशन, महाप्रबंधक, भारत संचार निगम लिमिटेड, कमाण्डेंट छठी बटालियन राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, एनसीसी निदेशक, जयपुर एयरपोर्ट निदेशक इत्यादि अधिकारीगण उपस्थित थे। सभी अधिकारीगण ने बैठक में आपसी समन्वय से मॉक ड्रिल संपन्न करने हेतु प्रतिबद्धता जाहिर की।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देशों की पालना में मंगलवार को मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में राज्य के समस्त संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक एवं सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारियों की वीसी के माध्यम से बैठक आयोजित की गई।